खुलेपन की नीतियों की दरकार

बी.आर.शिनॉय

(B.R. SHENOY – ECONOMIC PROPHECIES)

(21 दिसंबर 1961)

इस लेख में चुनाव से ठीक पहले जारी राजनैतिक दलों के घोषणापत्रों की आलोचना की गई है। लेखक के मुताबिक केवल जनसंघ का घोषणा-पत्र ही अर्थव्यवस्था के सरकारीकरण के खिलाफ है। हालांकि इसमें बी आधारभूत मामलों को लेकर स्पष्टता का अभाव ही है। पीएसपी और कांग्रेस जिस प्रगति की बात कर रहे हैं, वह केवल कुछ अतिप्रिय हठों को दूर करके ही हासिल की जा सकती है।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) के घोषणापत्र के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक अंतर को और अधिक बढ़ा दिया है। उसने पहले से मौजूद शक्तिशाली परिवारों में नवधनाढ्यों का एक और नया वर्ग जोड़ दिया है। योजनाओं से ये 'भारी लाभ कमाने वाले' 'संपत्ति की मलाई' को बांट रहे हैं और उत्पादन का तरीका भी उनकी जरूरतों को पूरा करने में जुटा हुआ है। लोगों पर भारी बोझ के बाद भी, हमारे पास जनकल्याण और रोजगार के नाम पर 'दिखाने के लिए मामूली सी उपलब्धियां' हैं। राष्ट्रीय शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं होने के साथ ही लोगों के जीवनस्तर में 'बड़े पैमाने पर गिरावट' देखी गई है। ये ही आरोप, इस पर जोर देने को लेकर हल्के से अंतर को छोड़कर, कम्युनिस्टों, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टियों के घोषणापत्र के बारे में भी लगाए जा सकते हैं।

कांग्रेस के घोषणापत्र में आरोपों से बचाव के जो उपाय किए गए हैं, वे संतुलन और ताकत दिखाते हैं। वह यह मानता है कि गरीबी अभी काफी बाकी है, बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर है और बड़े लक्ष्यों और मंशा के बाद भी विसंगतियां कायम हैं और कई बार तो यह बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन, गलतियों और भूलों, राष्ट्रीय आपदाओं और शीतयुद्ध के बावजूद 'भारतीय लोगों का तीर्थयात्रा के अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ना' जारी है, जो कि भारी, बड़े, छोटे उद्योगों के विकास में देखा जा सकता है। किसानी के

तौरतरीकों में 'उल्लेखनीय' सुधार हुआ है और कृषि उत्पादन में भी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा इंसानी गतिविधियों की विभिन्न विधाओं में तरक्की साफ देखी जा सकती है।

हालांकि औद्योगिक उत्पादन चौंकाने वाला है- पिछले नौ सालों में औद्योगिक उत्पादन सालाना 7.6 फीसदी तक पहुंच गया है। यह कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और अमेरिका से डेढ़ से दो गुना ज्यादा है। यह जंग में हासिल जीत की तरह है, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जहां तक गुणवत्ता और मूल्य की बात है तो भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी देशों के आगे नहीं टिक पाता। हमारे उत्पाद बिना बड़े घाटे के विदेश में नहीं बेचे जा सकते। यह बात और है कि इस घाटे की भरपाई हम घरेलू बाजार में मूल्यों पर नियंत्रण और निर्यात को बढ़ावा देकर और आयात लाइसेंस से करने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम घरेलू उपभोक्ता को झेलना पड़ता है।

किसी भी सरकार को अपने राजस्व का एक हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इस विशेष काम के नाम पर धन मुहैया कराने के लिए प्रयास भी अभूतपूर्व होना चाहिए। हम इंसान से ज्यादा तो इस्पात में निवेश कर रहे हैं..

उद्योगों का विकास कृषि की ही कीमत पर किया गया है। 1955-56 में योजनाओं में तेजी के साथ ही कृषि उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया है। यह आबादी में इजाफे के साथ सालाना 1.5 फीसदी या कई बार इससे कम विकास दर दिखाता रहा है। संपूर्ण उत्पादन और खाद्य सामग्री व कपड़े की खपत की तुलना में कृषि तकनीकों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धि नगण्य है।

कांग्रेस का घोषणापत्र इन तीन उपलब्धियों की बात करता है। जो कांग्रेस की राय में इस बहुआयामी पृष्ठभूमि में भी 'साफ देखी' जा सकती हैं। पहली स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में 1950-51 के 24 मिलियन की तुलना में वर्तमान का 46 मिलियन तक का इजाफा। दूसरी उपलब्धि 40 के दशक की 32 की तुलना में औसत आयु में 47.5

तक का इजाफा। तीसरा सामुदायिक कार्यक्रमों के जरिये पंचायती राज्य की स्थापना, जिसके तहत 72 फीसदी गांव और 50 फीसदी आबादी आ जाती है।

स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में इजाफे का पूरा श्रेय प्रशासन ही नहीं ले सकता। कुछ इजाफा तो निजी क्षेत्र के प्रयासों का नतीजा है, कुछ नगर निगमों और अन्य अर्ध-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का। किसी भी सरकार को अपने राजस्व का एक हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इस विशेष काम के नाम पर धन मुहैया कराने के लिए प्रयास भी अभूतपूर्व होना चाहिए। हम इंसान से ज्यादा तो इस्पात में निवेश कर रहे हैं। दूसरी योजना में केंद्र और राज्यों ने शिक्षा पर 208 करोड़ रुपए खर्च किए थे जबकि इस्पात के तीन सार्वजनिक क्षेत्रों के प्लांटों पर खर्च की योजना 562 करोड़ रुपए की थी। कुल खर्च में फीसदी के लिहाज से देखा जाए तो शिक्षा के मामले में पहली योजना के 1.9 फीसदी से गिरकर यह दूसरी योजना में 1.5 फीसदी हो गया। औसत आयु में इजाफे का अधिकांश श्रेय डीडीटी अभियान और अन्य स्वास्थ्य उपायों को जाना चाहिए। ऐसा होने पर बिना किसी सरकारी योजना के ही अन्य देशो में भी औसत आयु में इजाफा देखा गया है। इसमें बेहतर खाद्य और बेहतर जीवन की परिस्थितियां दिखाई नहीं देती। हमारी खाद्य सामग्री और कपड़ों की खपत अर्द्ध स्थिर (semi-stagnant) और निम्नस्तरीय है।

सरकारी योजनाएं लाइसेंसों, कांट्रेक्ट्स, परमिट्स, कोटा और रियायतों के जरिये काम करती हैं। वे बिना किसी नैतिक या आर्थिक नाम के ही बड़ा और आसान फायदा लाती हैं। पिछले दशक की आर्थिक अराजकता और नैतिक पतन का कारण इनमें ही छिपा है। पीएसपी अब तक की तुलना में इन पर व्यय को और अधिक विस्तार देना चाहती है।

सहकारिता की ही तरह सामुदायिक विकास और पंचायती राज में भी अनेक संभावनाएं हैं। जहां इसमें कामयाबी मिली है वहां परिणाम इसकी पुष्टि भी करते हैं। जब आर्थिक

मदद कोई बाधा न हो तो कामयाबी लोगों की काबिलियत, उत्साह और चरित्र पर निर्भर करती है। इन तीनों की ही बेहद कमी देखने को मिलती है। ईकाइयों की संख्या में इजाफे को तरक्की का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वास्तविकता में तो इसमें एकाएक इजाफे ने संदेह को ही जन्म देना चाहिए। प्रगति का आकलन तो कृषि उत्पादन में सकल वृद्धि से ही लगाया जाना चाहिए। ऐसा अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा।

पीएसपी का घोषणापत्र हालांकि यह बात स्वीकारता है, 'योजनाओं का आकार जितना बड़ा होता जाता है, उससे फायदा उतना ही कम होता जाता है।' यह रोजगार में गिरावट, कीमतों की स्थिति और कमाई में विषमता में पिछली योजनाओं की वजह से संबंध देखता है। यह इंसान के सरकारीकरण, प्रतिस्पर्धा के गुणों का विरोध करके ईईसी की तेज विकास की संभावना का उदाहरण देता है। फिर भी यह एमआईए का और अधिक आर्थिक व सामाजिक समन्वित योजनाओं से निवारण करना चाहता है। यह आधारभूत विरोधाभास समझ से परे है।

सरकारी योजनाएं लाइसेंसों, कांट्रेक्ट्स, परमिट्स, कोटा और रियायतों के जरिये काम करती हैं। वे बिना किसी नैतिक या आर्थिक नाम के ही बड़ा और आसान फायदा लाती हैं। पिछले दशक की आर्थिक अराजकता और नैतिक पतन का कारण इनमें ही छिपा है। पीएसपी अब तक की तुलना में इन पर व्यय को और अधिक विस्तार देना चाहती है। यह न तो इससे होने वाले बेमतलब के फायदों को लेकर कुछ करने वाली है और न ही अर्थव्यवस्था पर इसके बुरे असर या एकाधिकारों के हस्तांतरण के कारण कुछ क्षेत्रों के एक सीमित दायरे में सिमटने को लेकर ही वह कुछ करने का ही आश्वासन देती है। न्याय के लिए कानून के राज के तहत मुक्त और व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा से बेहतर इंसान के लिए कोई गारंटी हो ही नहीं सकती।

जनसंघ के घोषणापत्र में सुस्पष्टता का अभाव है। हालांकि यह सरकार के पूर्ण नियंत्रण का विरोध करता है। यह मूलतः योजना को बदल देगा। योजना आयोग को सलाहकारों के एक विशेषज्ञ संगठन में बदल देगा। सार्वजनिक क्षेत्र को केवल रक्षा तक ही सीमित कर देगा। कुछ 'आधारभूत' उद्योगों को एकाधिकार दे देगा। सरकारी खर्च को कम कर देगा और करों के बढ़ते बोझ से कुछ राहत देगा। कीमतों का तंत्र हालांकि आजाद होगा,

लेकिन कृषि उत्पादों के लिए मूल्य समर्थन की व्यवस्था रहेगी। अब तक कोई ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है जो यह आश्वस्त कर सके कि इन उपायों से मुद्रास्फीति हो सकती है।

सरकारीकरण (स्टेटिज़्म) के विरोध के बावजूद कई बिंदुओं पर सरकार का हाथ साफ तौर पर देखा जा सकता है। जमीन पर हदबंदी लागू रहेगी। निजी आय में बढ़ोतरी को लेकर 2000 रुपए प्रति माह की हद होगी और 125 रुपए प्रति माह का सैलरी फ्लोर भी रहेगा। आयात में, खासतौर पर टॉयलेटरी और विलासिता के सामान के, काफी हद तक कटौती होगी। रोजगार का विकल्प मिलने तक कोई छंटनी नहीं होगी। हर नागरिक को न्यूनतम जीवनस्तर की गारंटी, सभी को मुफ्त स्वास्थ सेवाएं और रोजगार की गारंटी तत्काल तो असाध्य ही लगती है।

स्वतंत्र पार्टी का घोषणापत्र गांधीजी की कम जिम्मेदारी की संकल्पना पर आधारित है। 'ज्यादा प्रतिस्पर्धा' और 'कम नियंत्रण' को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पार्टी सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप को खत्म कर देगी। सार्वजनिक क्षेत्र सहित सभी जगह एकाधिकार खत्म कर दिया जाएगा। अफसरशाही के विस्तार, सरकारी खर्च पर अंकुश लगेगा। योजना आयोग समाप्त कर दिया जाएगा और कारोबारी जगत को अत्याचारपूर्ण नियमों से मुक्ति मिलेगी। यह घोषणापत्र राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था तंत्र का समर्थन करता है। सोवियत संघ की तरह भारी उद्योगों के खिलाफ है। यह कृषि क्षेत्र और उपभोक्ता सामग्री उद्योगों की अनदेखी का भी विरोध करता है।

सरकार की गांधीवादी कल्पना संभवतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कटौती में मददगार होगी। भूमि राजस्व का लगभग खात्मा हो जाएगा। इससे संभव है कि कीमतों में स्थिरता आए और रुपया और अधिक ईमानदार हो जाएगा, अगर कृषि को समर्थन मूल्य के मुद्रास्फीति वाले जाल से खिलवाड़ नहीं किया गया तो। आयात प्रतिबंधों के हटाने से-शून्य मुद्रास्फीति से एक आसान कदम-कस्टम राजस्व में भारी इजाफा हो सकता है। जो सामान अब तक स्मगल होता था आयात शुल्क के भुगतान के साथ देश में आएगा। नियंत्रण हटा लिए जाने से बलप्रयोग के कारण की जाने वाली काली कमाई और कर चोरी भी समाप्त हो जाएगी। सामान्य बजट संसाधनों के साथ मिलकर यह हो सकता है कि सरकार

के मुख्य कामों के लिए और अधिक वित्त उपलब्ध करा दे।

हमें कल्याण के उपायों और कल्याण के बीच में से एक को चुनना होगा। कानून के जरिये समृद्धि एक छलावा और जाल सा है। यूके में पिछले आठ सालों में वास्तविक पारिश्रमिक में लगभग 17 फीसदी का इजाफा हुआ। यही धीमी गति ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन और अन्य 'कल्याणकारी' देशों में भी देखने को मिली। इसी काल में ईईसी देशों, इजरायल और जापान में मुक्त अर्थव्यवस्था के तहत पारिश्रमिक और राष्ट्रीय आय में जबर्दस्त तरक्की देखने को मिली। इजरायल में तो यह दोगुनी हो गई। दूसरे देशों में भी इसमें 60 फीसदी से ज्यादा का इजाफा देखा गया।

चुनिंदा जगहों पर ही सुधार लागू करके कांग्रेस और पीएसपी के आर्थिक कार्यक्रमों को तेज गति की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो अड़ियल मतों और विचारों की ही चीरफाड़ करनी होगी। जनसंघ के कार्यक्रम के साथ शायद ऐसा संभव है। स्वतंत्र पार्टी का घोषणापत्र भी उन नीतियों के करीब ही आता है जो इस वक्त सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बेहद फायदेमंद साबित हो रही हैं, जहां भी उन्हें अपनाया गया है। लोकप्रिय सोच के विपरीत इन नीतियों को आजाद दुनिया में स्वीकृति मिल रही है।